

प्रेषक,

डी०पी० गैरोला,
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 04-मार्च, 2013

विषय- मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान में न्याय लिपिक संविदा/आउटसोसिंग के 09 पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-91/XXXVI(I)/2012-234/2001 दिनांक 26-04-2012 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल के अधिष्ठान में न्याय लिपिक संविदा/आउटसोसिंग के 09 पदों के कार्यकाल को वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाय, दिनांक 01-03-2013 से दिनांक 28-02-2014 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-102-उच्च न्यायालय-03-उच्च न्यायालय-00" की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं०-177 NP/XXVII(5)/2012-13 दिनांक 27-02-2013 को प्राप्त उनकी सहमति के से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

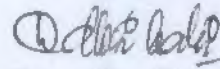
(डी०पी० गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्या- 67(1)/XXXVI(2)/2013-234/2001 तददिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 3- वित्त अनुभाग-5/कार्मिक अनुभाग/एन०आई०सी०/गार्ड फाईल।

आज्ञा से


(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव